17–18 फरवरी, 2018 को पटना में छठे राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, भारत क्षेत्र में माननीय अध्यक्ष का उद्घाटन भाषण

1. राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (CPA, India Region) के छठे सम्मेलन में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं इस सम्मेलन में पहली बार आए हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा एवं गुजरात के नवनिर्वाचित विधान मंडलों एवं परिषदों के अध्यक्षों एवं सभापतियों का अभिनन्दन करती हूं।

2. मैं इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का हार्दिक अभिनन्दन करती हूं। उनकी राजनीतिक परिपक्वता, समझ एवं जनजुड़ाव कोई परिचय का मोहताज नहीं। **माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्रित्वकाल में बिहार की विकास दर काफी उत्साहजनक रही है। ''न्याय के साथ विकास'' की उनकी अवधारणा है। इसी उद्देश्य से बिहार की जनता को सुशासन देने का उन्होंने सुनियोजित प्रयास किया है। शराबबन्दी एवं बिजली क्षेत्र में सुधार इस सरकार की उल्लेखनीय उपलब्धि रही है। बिहार में सामाजिक सुधारों की दिशा में काफी कार्य हुआ है। शराबबन्दी के कारण नागरिकों के स्वास्थ्य में बेहतरी, परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार, पारिवारिक हिंसा, घरेलू कलह एवं सामाजिक अपराध में कमी परिलक्षित हो रही है। दहेज प्रथा के विरुद्ध मानव श्रृंखला के निर्माण द्वारा लोगों में इस विषय के प्रति जनजागृति लाई गई है। विश्वास है कि उनके नेतृत्व में सुख और समृद्धि राज्य के जन–जन तक पहुंचेगी।**

3. I extend a hearty welcome to Hon. Emilia Monjowa Lifaka **(एमिलिया मोंजावा लिफाका)**, Chairperson of Executive Committee of CPA, Shri Akbar Khan, Secretary General, CPA and distinguished guests from various member countries of CPA and I wish them a pleasant stay in India.

4. CPA, India Region Conference के आयोजन एवं शानदार मेहमानवाजी के लिए बिहार विधान सभा के अध्यक्ष श्री विजय चौधरी और बिहार सरकार को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद।

5. पाटलिपुत्र उर्फ पटना–शाश्वत भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का उद्‌गम स्थल, गौरवशाली इतिहास, परंपरा एवं संस्कृति। ज्ञान, शिक्षा, सभ्यता एवं लोकतंत्र की जन्म एवं कर्मभूमि।

6. बिहार – भगवान बुद्ध, महावीर, अशोक, चाणक्य, आचार्य नागार्जुन, आर्यभट्‌ट, भास्कराचार्य, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, श्री जयप्रकाश नारायण, रामधारी सिंह दिनकर – ज्ञान, विज्ञान, कला, सभ्यता, संस्कृति, लोकतंत्र, दर्शन एवं अध्यात्म से जुड़े महान व्यक्तित्व।

7. CPA, India Region का यह छठा सम्मेलन – प्रभावी एवं सार्थक होगा। 2015 में पिछली बार हम गोवा सम्मेलन में मिले थे। विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चाएं हुई थी। उस सम्मेलन का मुख्य विषय था संसदीय लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण (Strengthening of Parliamentry Democracy)।

8. इस सम्मेलन की Theme - Role of Parliament and Parliamentarians in achieving Sustainable Development Goals अत्यन्त प्रासंगिक एंव समसामयिक है। ''विकास के कार्यक्रम में सांसदों की भूमिका (Role of Parliamentarians in development agenda)'' तथा 'विधायिका और न्यायपालिका – लोकतंत्र के दो महत्वपूर्ण स्तम्भ (Legislature and Judiciary – two important pillars of democracy)' अन्य विषय हैं, जिन पर हम अगले दो दिनों में चर्चा करेंगे।

9. SDG – 17 Goals and 169 Targets – to be achieved by 2030. विश्व में गरीबी और भुखमरी दूर करना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण – मुख्य उद्देश्य।

10. अगर हम ध्यान से SDG पर चिंतन करें तो हम देखेंगे कि यह हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे तौर–तरीके, तहजीब का एक International reflection ही है। भारत में प्राचीन काल से आज तक परिवार में, समाज में जिन बातों को बताया, सिखाया और अनुकरण किया जाता है, उन सब बातों का समावेश SDG में है। SDG में विकास में sustainability की बात की गई है और Sustainability भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है।

11. प्राकृतिक संसाधन, नदी–नाले, जीव–जन्तु, पेड़–पौधे, भारतीय परिवारों में सबके पालन की चिन्ता एवं व्यवस्था होती है। प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों से हमारा एक आत्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक एवं पारिवारिक संबंध। नदियों, वृक्षों और पशुओं की पूजा।

12. हमारे यहां तो Sacred Grooves (पवित्र उपवन) की परंपरा है। देशभर में कई ऐसे पवित्र उपवन हैं जैसे गंधमार्दन, नैमिषारण्य, दंडकारण्य इत्यादि। इनमें स्वतः ही पर्यावरण के विभिन्न घटक पलते हैं।

13. Its clear from an old text of Sanskrit. I quote:-

''समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमंडले।

विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पाद।।''

14. वृक्षों की रक्षा के लिए उत्तराखंड में चिपको आन्दोलन के विषय में सभी लोगों ने सुना है और मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि पिछले एक वर्ष में भारत का total forest cover 1% (8021 Sq. Km.) बढ़ गया है।

15. आज भारत के विकास की धुरी SDG को प्रतिबिम्बित करती है। सरकार द्वारा Minimum Government Maximum Governance के तहत तमाम जनकल्याण से जुड़ी योजनाएं SDG से संबंधित हैं जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आधार से लिंकिंग, नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी (SDG No. 3), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना (SDG No. 5), स्वच्छ भारत अभियान, (SDG No. 6), प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (SDGs No. 3&7), प्रधानमंत्री आवास योजना (SDG No. 8)। ये अपने–आप ही SDG के किसी न किसी गोल्स को टारगेट करती हैं। ऐसी कई योजनाएं जैसे Digital India, Make in India, Stand Up India, Start Up India, Adarsh Gram Yojana, Skill Development इत्यादि SDG को आगे ले जाते हुए game changer साबित हो रही हैं।

16. Climate Change सामने गंभीर समस्या – प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु चक्र परिवर्तन – गरीब एवं महिलाएं सर्वाधिक प्रभावित।

17. सरकार Green and Clean Energy और Organic Farming, Pollution Control,

18. Reduce, Reuse, Recycle

19. ''जीवने यावद् आदानं श्यात प्रदानं ततोधिकम्,

इत्येशाप्रार्थना अस्माकम् भगवन् परिपूर्यतम्।।''

20. SDG को हासिल करने में जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका क्योंकि ये जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को परिलक्षित करते हैं।

21. संसद सदस्य, विधानों, सदन में वाद–विवादों, संसदीय निगरानी, समिति की सुनवाई, सिविल सोसायटी संगठनों के साथ कार्य करके, बजट पर चर्चाओं के दौरान संबद्ध जानकारियाँ देकर, कार्यपालिका के साथ सहयोग करके तथा जागरूकता लाने के उद्देश्य से संगोष्ठियों, कार्यशालाओं तथा सम्मेलनों में सक्रिय भागीदारी करके इन लक्ष्यों के त्वरित कार्यान्वयन में मदद कर सकते हैं।

22. निर्वाचित प्रतिनिधियों का कर्त्तव्य – नीतियों और कार्यक्रमों का उचित कार्यान्वयन एवं समाज के हाशिये पर खड़े आखिरी व्यक्ति तक उनके लाभ पहुंचाना ताकि अन्त्योदय की मूल भावना चरितार्थ हो।

23. भारतीय लोकतंत्र जीवन्त एवं सशक्त है। संसद में चर्चा का स्तर और अधिक उन्नत करने एवं विषयों की जटिलता को सरल रूप में जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने के लिए 23 जुलाई 2015 को SRI की स्थापना। अभी तक 23 वर्कशॉप – विशेषज्ञों से संसद सदस्यों का संवाद।

24. 19 फरवरी 2017 को South East Asian Speaker's Summit में Indore Declaration में यह निर्णय लिया गया है कि SDG के महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर संसद के हर सत्र में चर्चा के लिए एक दिन नियत रखेंगे। हमारी संसद की सभा में नौ बार SDG के विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चाएं हुई हैं। मैंने अपनी ओर से सभी मुख्यमंत्रियों को भी अपने राज्य की विधानसभाओं में SDG पर चर्चा के लिए पत्र लिखा है और जिसके प्रति काफी उत्साहवर्द्धक response मिले हैं।

25. मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ – जनतंत्र एवं देशहित में मीडिया की सकारात्मक जिम्मेदारी। Media Workshop for positive and purposeful

reporting and understanding of the functioning of legislative bodies. इसी भावना से लोक सभा सचिवालय ने लोक सभा में SDG पर हो रहे विभिन्न कार्यक्रमों से उनको अवगत कराया गया। इससे मीडिया का SDG के प्रति एक रूझान बनेगा और वे इस क्षेत्र में हो रहे विभिन्न सरकारी और गैर–सरकारी प्रयासों की एक सकारात्मक रिपोर्टिंग करेंगे।

26. SDG के अलावा सम्मेलन में चर्चा का दूसरा विषय है 'विधायिका और न्यायपालिका – लोकतंत्र के दो महत्वपूर्ण स्तम्भ'। यह विषय भी अत्यन्त महत्वपूर्ण और रोचक है।

27. राष्ट्र के हितों के संरक्षक के रूप में, लोकतंत्र का प्रत्येक अंग किसी न किसी प्रकार से लोगों के प्रति जवाबदेह है। विधायिका चुनावों के माध्यम से लोगों के प्रति जवाबदेह है, विधायिका के माध्यम से कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है और एक प्रकार से न्यायपालिका भी लोगों के प्रति जवाबदेह है क्योंकि जनता के अधिकारों के एक संरक्षक के रूप में इसकी एकमात्र जिम्मेदारी संविधान की रक्षा करना है। इसकी परिकल्पना एक ऐसी संस्था के रूप में की गई है जो देश को शासित करने के लिए शक्तियों के अनावश्यक उपयोग पर अंकुश लगाती है।

28. हमारी सनातन धर्म व्यवस्था में सदाचार ही को प्रथम धर्म कहा गया है।

''यस्मिन् देशे यह आचारः पारंपर्यक्रमागतः।

वर्षानाम सान्तरालानां ससदाचार उच्यते।।''

29. धर्मनीति, लोकनीति, दंडनीति, राजनीति इसी के परिणित फल हैं। ''नहि सत्यार्थ परमो धर्मः अहिंसा परमो धर्मः'' यही धर्मयुक्त न्याय व्यवस्था का बीज मंत्र है। न्याय, समाज एवं राष्ट्र को नियमित कर, सुव्यवस्थित कर उसे सुचारू बनाता है। न्यायदंड के उपयोग से ही समाज में व्यवस्था स्थापित रहती है।

30. अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने लिखा हैः–

''तदेतत् क्षत्रस्य क्षत्रं यद्धर्मः। तस्माद्धर्मात्परं नास्ति।

अथो अबलीयान् बलीयांसमाशंसते धर्मेण। यथा राज्ञा एवम्।।''

(तात्पर्य यह है कि कानून राजाओं का राजा है, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता। राजा की शक्ति कानून की शक्ति के साथ मिलकर ताकतवर व्यक्ति से कमज़ोर व्यक्ति की रक्षा करती है। इसलिए हमें न्यायपूर्वक विधि का पालन करते हुए विधान मंडलों में काम–काज सम्पादित करना चाहिए।)

31. हमारे देश में विधानमंडलों ने न्यायपालिका की शक्तियों और अधिकारों का सदैव सम्मान किया है। हमारे विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों ने सदैव यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि न्यायपालिका के साथ उनके संबंध सदैव संविधान की मर्यादा एवं भावना के अनुरूप बने रहें। इसी प्रकार न्यायिक पुनरीक्षा के अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय न्यायपालिका को संवैधानिक संस्थाओं के बीच संविधान द्वारा अपेक्षित शक्तियों के पृथक्कीकरण और संतुलन को सुनिश्चित करना होगा।

32. भारत ने अपनी अनेकता और विविधता को अपने संस्थागत लोकतंत्र के साथ बहुत सफलतापूर्वक समायोजित कर लिया है। नीति तैयार करने की प्रक्रिया में सिविल सोसाइटी और नागरिकों के नेटवर्क का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। विशेषकर मीडिया और बौद्धिक संवाद के माध्यम से आलोचना और असहमति की अभिव्यक्ति हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। इस संबंध में संविधान सभा की बहस में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का यह वक्तव्य आज भी उतना ही सटीक एवं प्रासंगिक है।

"We have prepared a democratic Constitution. But successful working of democratic institutions requires in those who have to

work them, willingness to respect the view points of others, capacity for compromise and accommodation. Many things which cannot be written in a Constitution are done by conventions. Let me hope that we shall show those capacities and develop those conventions."

33. सुराज के बिना स्वराज अधूरा है। हम सब निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के मन में पक्ष–विपक्ष को लेकर मन में सवाल भी उठते हैं, नीतियों की निन्दा एवं प्रशंसा भी होती है, पर अपने लम्बे संसदीय अनुभव से मैं एक बात कहना चाहूंगी कि यह सब लोकतंत्र की शक्ति साबित होगा अगर हम सबके मन में पहला विचार निःस्वार्थ रूप से जन–कल्याण हो, अन्त्योदय हो।

34. No development is possible and sustainable unless it has a human face. As Pandit Deendayal Upadhayay ji, India's leading political and mass leader once said, 'Integral humanism is the basis for development as it espouses indigenous economic model that puts the human beings at a centre stage.'

35. एसडीजी विषय को लेकर यह कोई पहला सम्मेलन भी नहीं है और यह अंतिम भी नहीं है। SDG एक सतत् प्रक्रिया है और ऐसे आयोजन तभी जस्टिफाई होंगे जब हम मन से और वचन से अपने–अपने दायित्वों का पूर्ण निष्ठा से निर्वहन करेंगे। विकास की मशाल में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करेंगे।

36. विश्वास है कि आप लोगों के लिए यह चर्चा बहुत उपयोगी और प्रेरक साबित होगी। हम यहां चर्चा किए गए विषयों पर व्यापक जानकारी प्राप्त करके लौटेंगे। मैं बिहार सरकार और विधान सभा सचिवालय को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने बड़े गर्मजोशी से हमारा आतिथ्य सत्कार किया और सम्मेलन के लिए उत्कृष्ट व्यवस्था की।

धन्यवाद।